

(एन अधिकाय अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्रों में यात्रा सरकार द्वारा निर्धारित प्रकृतियों पर सुरक्षा/अधिनियम किया जाने है।)

### FORM-I

(For linear projects)

Office of the District Collector Dehra Dun

Government of Uttarakhand

No

Dated 07-03-2015

### TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4170 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Lakshyar-Ludhara-Kyari-Kachta Motor Road(4.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Mehmasa/Kyari village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4170 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V<sup>th</sup> annexure 23.2, 23, 23.1

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(Ravi Nath Rawan)

**FORM-II**

**(for projects other than linear projects)**

Office of the District Magistrate

Government of Uttarakhand

No

Dated 07.03.2015

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.417 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Lakshyar-Ludhara-Kyari-Kachra Motor Road(4.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Meharsa/ Kyari village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.417 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1

- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of KVARA..... villages(s) is enclosed as annexure 3b, 3c To annexure 3d, 4

- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(Ravipath Kaman)

District Magistrate  
Dehra Dun.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 07.03.2015 at time 12.00 P.M. at Dehradun in which application claiming rights in measuring 1.417 Area hect for the construction of LAKSHYAR-LUDHARA-KYARI-KACHTA MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Dehradun

Dated:..07/03/2015

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee  
(Ravi Nath Raman)  
District Magistrate  
Dehra Dun.

## कायवत

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकारी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पधारण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक सं० 11-09/98-FC(P) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07/3/15 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर मत अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ-

जनपद- देहरादून के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार- बुधवा-क्यासी-कवटा हठवा मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन किमी० 11 से 14 एवं विस्तार 15 से 18 निर्माण हेतु 1.417 हे० वनभूमि के गैर वाणिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 184 वृक्षों के पालन की अनुमति हेतु अधि०.नॉ०नि०वि० सहित को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6 (1) के अनुसार उम्मी, क्यासी, ग्राम सभा के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 11-11-2014 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्सारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 27.2.15 को विचार विमर्श कर निस्सारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान में विद्यमान स्थिति में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि वकालत वनप्रमाण की विवर रजिस्टर के अन्तर्गत स्थित सौयम वन भूमि में स्थित भू-भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वनअधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अतः में बैठक बन्दवाह के साथ सम्पन्न की गयी।

जिला सम्मान कल्याण अधिकारी  
देहरादून  
सदस्य सचिव

प्रमाणित वन अधिकारी  
प्रमाणित वन अधिकारी  
सदस्य  
वकालत वन प्रमाण वकालत  
देहरादून

जिलाधिकारी  
अध्यक्ष  
देहरादून

District Magistrate  
Dehra Dun

50

है।  
की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती का दावा/आवेदन पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समिति/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए संबंधित उप प्रमानीय वनाधिकारी, वकराला द्वारा अनुरोधित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन गाई है।

समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सांविजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरोध की रखा गया। ग्राम समिति के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तमिति का संबंधित ग्राम खण्ड लोक निर्माण विभाग सहित के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष आरक्षित वन भूमि, 14.17 है 80 सिलबल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है 80) अर्थात् कुल 2.800 है 80 का अर्थात् के नव निर्माण हेतु 1.417 है 80 वन भूमि लो10नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है 80 विधानसभा क्षेत्र वकराला के ग्राम लखस्यार-गुवेरा-क्यासी कवट मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 15-18 तक मार्ग बैठक की कायदावादी प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के उपखण्ड स्तरीय माननीय सदस्यों का बैठक में स्थानित करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से

- 1- श्री अशोक पाण्डेय, उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून
  - 2- श्री डी.डी. मल्लिकार्जुन, उपप्रमानीय वनाधिकारी, वकराला वन प्रभाग वकराला
  - 3- श्री मिटन लाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी
  - 4- श्री राजेश नीटियाल, बी0डी0सी0 क्षेत्र - लाठल
- (सदस्य) (सदस्य/सचिव) (सदस्य) (अध्यक्ष)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।  
जिलाधिकारी कालसी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक पाण्डेय, उप अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम की कायदावादी का विवरण:-

2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-कालसी) की दिनांक 11.11.2019 को सम्पन्न बैठक किये जाने हेतु अनुरोधित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, अर्थात् कुल 2.800 है 80 वन भूमि) का अर्थात् लोक निर्माण विभाग सहित के पक्ष में हस्तान्तरित (ग्राम) है 80 आरक्षित वन भूमि, 14.17 है 80 सिलबल एवं सोयम वन भूमि, 1.383 है 80 नापभूमि (वन पंचायत भूमि, किमी0 18 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.417 है 80 वन भूमि लो10नि0वि0 को हस्तान्तरण।  
देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार-गुवेरा-क्यासी कवट मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत - जनपद प्रमाण-पत्र

## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

### कायदालय उपजिलाधिकारी कालसी

पारियोजना का नाम :- जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार-गुवेरा-क्यासी-कवट मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से किमी0 18 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.822 है 80 वन भूमि लो10नि0वि0 को हस्तान्तरण।

उप निगाहकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-कालसी  
जनपद-देहरादून

प्रतिनिधि :- निगाहकारी, देहरादून, को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप निगाहकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-कालसी  
जनपद-देहरादून

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत मा 10 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराला के विकासखण्ड कालसी में लखस्यार गुंथेरा क्यारी कचरा मार्ग के विस्तार किमी 15 से 18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.417 हे० वन भूमि ली०नि०वि० को हस्तांतरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वनभूमि, 1.417 हे० सिविल सोयम भूमि, नापभूमि 1.383) अर्थात् कुल 2.800 हे० को अखण्ड, ली०नि०वि० सहित के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



ग्राम प्रधान क्यारी  
ह/0-



प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

आपत्ति नहीं है।

के विस्तार कि०मी० 15-18 तक मार्ग का नवनिर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई 2.80 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को लखस्यार गुंथरा क्यारी कचटा मार्ग (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 1.417 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है०) अर्थात् कुल ग्राम सभा की सिकरिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा है।

लौ०नि०वि०, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारी के ग्रामवासियों को उचित वन भूमि अ०ख०, वर्ग के उपरान्त ग्राम सभा क्यारी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिसमें कार्य नहीं किया जा रहा है।

किया गया कि उचित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत वर्ग की गई। यह कि वन अधिकार सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ०ख०, लौ०नि०वि०, सहिया द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में उचित प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी द्वारा दिनांक 11.11.2014 को सम्मन् ग्राम द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आरक्षित वन भूमि, 1.417 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है०) अर्थात् कुल 2.80 है० हेतु 1.417 है० वन भूमि लौ०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० में लखस्यार गुंथरा क्यारी कचटा मार्ग के विस्तार कि०मी० 15-18 तक मार्ग के नव निर्माण उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराला के विकासखण्ड कालसी

### ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नाम:- जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार-गुंथरा-क्यारी-कचटा मोटर मार्ग का विस्तार कि०मी० 15 से कि०मी० 18 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.417 है० वन भूमि लौ०नि०वि० को हस्तान्तरण।

तहसील-कालसी, जिला-देहरादून

ग्राम पंचायत क्यारी

कार्यालय

पृष्ठ-30.3



श्री ५५५  
- ०३

| क्रमांक | ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ आमवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|
| १-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| २-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ३-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ४-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ५-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ६-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ७-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ८-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ९-      | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १०-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| ११-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १२-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १३-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १४-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १५-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १६-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १७-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १८-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| १९-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |
| २०-     | श्रीमान श्री गुरुदास                          |           |

दिनांक :- ११.११.२०१४ को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्रामपंचायत - क्यारी

[illegible]